VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
19 AUG 2019
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1244)

Name of Candidate	Bhanu Pratap Singh		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	635609
Center	MN	Date	19/08/19

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Discuss the need of an Independent Fiscal Council (IFC) in bringing about transparency and accountability in fiscal processes in India. **(150 words) 10**

भारत में राजकोषीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का समावेश करने हेतु एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद (IFC) की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

बेहतर राजकोषीय प्रबंधन हेतु गठित एन. के. सिंह समिति ने स्वतंत्र राजकोषीय परिषद (IFC) के गठन की अनुशंसा की है।

IFC की आवश्यकता

1) वर्तमान में बढ़ते राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण हेतु।

2) राजकोषीय बजट प्रबंधन एवं उत्तरदायित्व अधि. (FRBM Act) के कार्यान्वयन हेतु

3) राजकोषीय नीति में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता हेतु

IFC की मदद से पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का समावेश निम्न प्रकार होगा:-

- IFC हितों के टकराव को रोकर एक पारदर्शी प्रक्रिया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को जन्म देगी।

- इसके अलावा ऋण - GDP अनुपात में कमी लाकर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को मजबूत करेगी।

- राजकोषीय मानकों से विचलन दिखाने वाले राज्यों को दण्ड व अच्छा प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन देगी।

- स्वच्छ प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान संभव हो सकेगा।

कुल मिलाकर IFC वर्तमान समय की मांग है, जो बेहतर पारदर्शी एवं खुली नीतियों हेतु आवश्यक है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Recognizing the potential of exports in generating employment, a number of steps need to be taken to address India's weakening export competitiveness. Analyze. **(150 words) 10**

रोजगार सृजन हेतु निर्यात क्षेत्र की क्षमताओं की पहचान करते हुए, भारत की कमजोर होती निर्यात प्रतिस्पर्धा को संबोधित करने हेतु कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

वर्तमान में बेरोजगारी की दर पिछले 40 वर्षों में सर्वाधिक है, जो निर्यात जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन की जरूरत पर बल देती है।

निर्यात क्षेत्र की क्षमताएँ में भारत में सेवाओं के साथ वस्तुओं के निर्यात को आधार बनाया जा सकता है। नीति आयोग ने 2022 तक 800 बिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा है।

इस दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार की संभावना बढ़ेगी लेकिन इस हेतु कौशल, शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ-साथ अवसंरचना ढांचे पर जोर देने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्यात क्षेत्र की क्षमताओं में जनांकिकी लाभांश, वहनीय एवं सस्ते मानव उत्पादन करने की भारत की क्षमता प्रमुख है।

कमजोर होती प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाने हेतु कदम :

- निवेश बढ़ाने की जरूरत है ताकि उत्पादन बढ़ सके। (निजी + सार्वजनिक)
- कौशल विकास पर जोर
- ऊर्जा संरक्षण व आधारभूत ढाँचे पर जोर
- बचत को उत्पादक कार्यों में लगाना।

सार यही है कि अगर भारत को 5 T$ की अर्थव्यवस्था बनाना है तो निर्यात पर फोकस करना होगा।

3. Highlighting the main features of National Mineral Policy, 2019, discuss how it can help in ensuring sustainable and responsible mining.

(150 words) 10

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, चर्चा कीजिए कि यह संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करने में कैसे सहायता कर सकती है।

खनिजों का संधारणीय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खनिज नीति-2019 पारित की गई।

विशेषताएँ

- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर खनिज उत्पादन में वृद्धि करना।
- एकल लाइसेंसिंग पॉलिसी के माध्यम से खनिजों का महत्तम निष्कर्षण सुनिश्चित करना तथा रोजगार को बढ़ावा देना।
- पट्टे का आवंटन होते ही सरकारी हिस्से का राजस्व देना ताकि राजकोषीय स्थितियाँ मजबूत हो सकें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संधारणीय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण खनन में NMP-19 के प्रावधान व संभावना

⇒ इसमें खनिज कंपनियों पर यह दायित्व डाला गया है कि वह संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं पर्यावरणीय कार्यों को अंजाम देगी।

⇒ इसके अलावा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व कंपनी का होगा।

⇒ इस हेतु रॉयल्टी एवं अतिरिक्त सेस का प्रावधान है।

कुल मिलाकर NMP-19 आर्थिक लाभ के साथ-साथ पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Highlighting the salient features of the PM JI-VAN Yojana, analyze how it can assist in achieving the vision and goals of the National Policy on Biofuels, 2018. **(150 words) 10**

"प्रधानमंत्री जी-वन योजना" की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, विश्लेषण कीजिए कि यह जैव ईंधन राष्ट्रीय नीति, 2018 की दृष्टि और लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है।

PM JI-VAN (प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल अवशेष निपटान योजना) अपशिष्ट की मदद से जैव ईंधन बनाने पर जोर देती है।

विशेषताएँ

⇒ यह योजना 'waste to energy' की अवधारणा पर आधारित है।

⇒ योजना से जैव-ईंधन के साथ-साथ पराली दहन जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

⇒ योजना पेट्रोलियम रिफाइनरियों की मदद से जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाकर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

PM-JIVAN योजना राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (NBFP-18) के दृष्टिकोण व लक्ष्यों के अनुकूल है

- NBFP-18 2G तथा 3G पीढ़ी के ईंधनों की वकालत करती है। अत: PM-JIVAN भी 2G ~~उत्पा~~ जैव ईंधन को संवर्धित
- NBFP-18 में आयातित से अलग उत्पादन पर बल दिया गया है अत: PMJIVAN इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।
- NBFP-18 2G रिफाइनरियों की स्थापना पर बल देती है।

सार यही है कि भारत को हरित राष्ट्र बनाने में यह नीति कारगर है।

5. Zero Budget Natural Farming (ZBNF) provides an alternative to capital and chemical intensive agriculture currently being practiced in India. Analyze. **(150 words) 10**

जीरो बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF), भारत में वर्तमान समय में प्रचलित पूंजी और रसायन गहन कृषि का एक विकल्प प्रदान करती है। विश्लेषण कीजिए।

ZBNF ऐसी कृषि प्रणाली है, जिसमें न्यूनतम निवेश से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी की जा सकती है।

वर्तमान भारत में कृषि अत्यधिक पूंजी निवेश व कीटनाशकों व उर्वरकों, रसायनों पर आधारित है जबकि ZBNF इसका निम्न प्रकार विकल्प देती है

1) बीजामृत - बीजों को गायर के गोबर व मूत्र से उपचारित करने से कवकरोधी, जीवाणुरोधी बनाया जाता है।

2) जीवामृत - इसमें मिट्टी में गाय का गोबर डाला जाता है। ∴ रसायनों की जरूरत नहीं

3) वफासा - मिट्टी को वायु से ● गुजारा जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4) मल्चिंग - इससे मृदा में नमी, उर्वरता बार में कमी होती है।

इसी कारण नीति आयोग ने ZBNF की वकालत भी है। यह पूंजी व रसायनों के स्थान पर परंपरागत ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग करके कृषि को लाभकारी बनाती है।

अतः जल - जागरूकता, रोजगार एवं आरोग्य जीविका के माध्यम से ZBNF के अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Marine life is facing 'irreparable damage' from the millions of tonnes of plastic waste which ends up in the oceans each year. In this context, examine the implications of plastic pollution on marine ecosystem and suggest some measures for addressing this problem. **(150 words) 10**

समुद्री जीवन, प्रति वर्ष समुद्र में पहुँचने वाले लाखों टन प्लास्टिक कचरे के कारण 'अपूरणीय क्षति' का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए और इस समस्या के समाधान हेतु कुछ उपाय सुझाइये।

वर्ष 2050 तक समुद्रों में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक अधिक होगा। यह समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीरता को दिखाता है।

प्रभाव

⇒ समुद्री जीवन प्रभावित होता है। यथा- मछलियों में गिल्स में प्लास्टिक का संचयन।

⇒ व्हेल, मेढक, जेलीफिश में माइक्रोप्लास्टिक के कारण किडनी फेलियर

⇒ समुद्रीजीवों का प्रजनन, विकास पर दुष्प्रभाव।

⇒ सी-फूड के माध्यम से यही प्लास्टिक मानवीय खाद्य-श्रृंखला में प्रवेश फलत: ~~[illegible]~~ जैव-संवर्धन होता है।

समाधान हेतु उपाय

- प्लास्टिक कचरे के निपटान हेतु 3R पर बल

3R
- Reduce
- Reuse
- Recycle

- प्लास्मोलिसिस जैसी तकनीकों की मदद से निपटान
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध (भारत द्वारा 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे की घोषणा)
- अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को कड़ाई से लागू करना।
- जागरूकता – सोशल मीडिया, नागरिक समाज, NGO का सहयोग।

सार यही है कि प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है जो लंबे समय तक बना रहता है। अतः 3R अपनाने पर बल देना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Write a short note on the evolution of Bharat Stage norms in India. Also discuss the significance and challenges posed by the planned introduction of BS-VI norms in India from the year 2020. **(150 words) 10**

भारत में भारत स्टेज मानकों के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साथ ही, वर्ष 2020 से भारत में BS-VI मानकों को योजनाबद्ध रूप से लागू किए जाने के महत्व और उसमें आने वाली चुनौतियों की भी चर्चा कीजिए।

(BS) → वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु भारत स्टेज मानक (BS stage) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार।

प्रदूषक तत्वों SO_2, N_2O, CO_2 CO में कमी होती जाती है

BS I → BS II → BS III → BS IV → BS V → BS VI (सीधे अप्रैल 2020)

गुणवत्ता बढ़ती जाती है।

(महत्व)

⇒ ग्रीनहाउस गैसों में कमी (CO_2, CH_4, N_2O, O_3 etc) → प्रदूषण में कमी → स्वास्थ्य बेहतर होगा।

⇒ INDC प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में मददगार → वर्ष 2030 तक GDP की उत्सर्जन गहनता को 30-35%

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कम करना।

⇒ वैश्विक पेरिस समझौता के अनुरूप।

चुनौतियाँ

⇒ ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत में वृद्धि ⇒ उत्पादन में कमी ⇒ मंदी

⇒ रोजगार में गिरावट

⇒ ग्राहकों पर प्रभाव ⇒ अत्यधिक वित्तीय भार

⇒ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की चुनौती।

⇒ उद्योग जगत को नुकसान।

इस प्रकार प्रभावी नीतियों एवं प्रोत्साहन द्वारा BS VI मानकों के लाभ - साथ इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. What are black holes? Highlight the challenges in imaging a black hole? How were these challenges overcome by the Event Horizon Telescope project? **(150 words) 10**

ब्लैक होल क्या हैं? ब्लैक होल के चित्रण (इमेजिंग) में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा इन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया?

ब्लैक होल ऐसे मृत तारे हैं जो अनंत द्रव्यमान व प्रकाश को अपने से बाहर जाने नहीं देते। चंद्रशेखर सीमा लिमिट के अनुसार वे तारे ही ब्लैक होल बनते हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है।

चित्रण में चुनौतियाँ

⇒ चूँकि प्रकाश इनसे बाहर नहीं आता अतः प्रकाश व फोटोन द्वारा चित्रण संभव नहीं।

⇒ इस हेतु गुरुत्वाकर्षण तरंगों (GW) की मदद से इनका पता लगाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⇒ लेकिन सिग्नल वीक होने से इन्हें पकड़ना मुश्किल।

हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल का चित्रण किया गया।

⇒ 16 रेडियो टेलीस्कोप का समूह

⇒ weak से भी weak संकेतों को पकड़ने हेतु विभिन्न टेलीस्कोपों का अत्याधिक जुड़ाव

⇒ GW सिद्धांत की नवीन व्याख्या।

आर नहीं है कि Black hole हमारे ब्रह्माण्ड का 90% से अधिक है। अतः इनके अध्ययन से ब्रह्माण्डीय रहस्यों से पर्दा हटाया जा सकेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. While mentioning the objectives of the Arms Trade Treaty (ATT), discuss the challenges which are hindering the utilization of the ATT to its full potential. **(150 words) 10**

शस्त्र व्यापार संधि (ATT) के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए, उन चुनौतियों की चर्चा कीजिए जो ATT को इसकी पूर्ण क्षमता से उपयोगित किये जाने में बाधक हैं।

शस्त्र व्यापार संधि के उद्देश्य इस प्रकार है! —

1) संपूर्ण विश्व में परमाणु हथियारों की दौड़ पर अंकुश लगाना।

2) संपूर्ण/पूर्ण निरशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना।

3) वैश्विक शांति को बढ़ावा देना।

4) UN चार्टर के अनुरूप शांति, कानून का राज्य, मानवाधिकार को सुनिश्चित करना।

चुनौतियाँ

ATT पर शक्तिशाली राष्ट्रों यथा —

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत, USA, चीन द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के इसकी पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं हो पा रहा है।

- हाल ही में USA व रूस के बीच संधि का टूट जाना भी चिंताजनक स्थिति पैदा करती है।

- ATT पूर्ण निरस्त्रीकरण उपलब्ध नहीं कराती है।

आर नहीं है कि ATT को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित होने वाला सभी देशों को इसका अनुमोदन करने की जरूरत है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Threats to internal security of India may be posed both through the communication networks and also to the networks. Discuss. Also, highlight the steps taken by the government in making the networks more secure.

(150 words) 10

भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा संचार नेटवर्कों के माध्यम से एवं स्वयं संचार नेटवर्कों को खतरा होने, दोनों ही प्रकार से हो सकता है। चर्चा कीजिए। साथ ही, नेटवर्कों को अधिक सुरक्षित बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए।

आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य बाह्य एवं आंतरिक खतरों की अनुपस्थिति

आंतरिक सुरक्षा — दोहरा खतरा

संचार नेटवर्कों के माध्यम से
⇓
स्पैम, वानाक्राई, पेट्या इत्यादि को इंजेक्ट, नेटवर्क के माध्यम से प्रवेश कराकर
⇓
गोपनीय व संवेदनशील डाटा को नुकसान पहुंचाया जाता है।

स्वयं संचार नेटवर्क को
⇓
खराब एवं विफल संचार संरचना
⇓
साइबर सुरक्षा के हमलों के जोखिम
⇓
फलत: संपूर्ण नेटवर्क की विफलता

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

दोनों ही खतरनाक

सरकारी कदम - भारत साइबर सीक्यूरिटी इंडेक्स
में 23वां स्थान

1) राष्ट्रीय साइबर नीति

2) CERT-IN की स्थापना

3) प्रत्येक जिले में साइबर-सेल की स्थापना।

4) स्वीकृत साइबर सुरक्षा हेतु सुपर कंप्यूटर मिशन को बढ़ावा।

5) NICCCC की स्थापना

सार यही है कि साइबर सुरक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है। इस हेतु सुदृढ़ आधारभूत ढांचे की जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Highlight the importance and challenges related to integration of Variable Renewable Energy (VRE) in India. Mention some steps that can be taken for its smooth integration with the synchronized Indian grid. **(250 words) 15**

भारत में परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (VRE) के एकीकरण के महत्व और इससे संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ऐसे कुछ कदमों का उल्लेख कीजिए जो समक्रमिक (सिंक्रनाइज्ड) भारतीय ग्रिड के साथ इसके सहज एकीकरण के लिए उठाए जा सकते हैं।

भारत द्वारा वर्ष 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है ताकि INDC प्रतिबद्धताओं एवं पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते-2015 को प्राप्त किया जा सके।

VRE का महत्व :-

- भारत विश्व का दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला देश है। अतः बढ़ती ऊर्जा मांगों की पूर्ति हेतु VRE की जरूरत है।

- निकट भविष्य में जीवाश्म ईंधनों यथा कोयला, पेट्रोल आदि के खात्मे के कारण VRE जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण एवं ग्रीनहाउस गैसों पर अंकुश VRE को आवश्यक बनाता है।

- नीति आयोग द्वारा 2022 तक 'New India' के सपने को साकार करने हेतु VRE जरूरी है।

VRE की मुख्य चुनौतियाँ इसका वहनीय, धारणीय, अवहनीय एवं आधुनिक नहीं होना है:—

- आपूर्ति निवेश के कारण आयात पर और उपकरणों की निर्भरता एक प्रमुख चुनौती है।

- आसान शर्तों पर ऋण की पहुँच न होना भी एक प्रमुख कारण है।

- भूमि अधिग्रहण, एकीकृत नीति का अभाव भी VRE के समक्ष नवीन चुनौती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

ऐसे कदम जो समकालिक भारतीय ग्रिड के साथ इसके सहज एकीकरण हेतु उठाए जा सकते हैं निम्न हैं: –

- एकीकृत नीतियों का विकास ताकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा का उत्पादन वहनीय हो।
- R&D पर निवेश ताकि नवीन तकनीकों को उपयोग में लाया जा सके।
- ग्रिड कनेक्टिविटी हेतु 5G व AI जैसी तकनीकों का प्रयोग।
- ग्रीन टैरिफ नीति को अपनाना।

निष्कर्ष: भारतीय विकास (SD) हेतु परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की मांग है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. There have been arguments that India could fall into a 'middle income trap'. Explaining the phenomenon, highlight the reasons behind such arguments. How can India avoid it? **(250 words) 15**

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि भारत 'मध्यम आय पाश' में फंस सकता है। इस परिघटना की व्याख्या करते हुए, ऐसे तर्कों के लिए उत्तरदायी कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत इससे किस प्रकार बच सकता है?

घरेलू उपभोग में कमी, वैश्विक मंदी, ट्रेड वार जैसे तर्कों के कारण हाल ही में 'मध्यम आय पाश' की संकल्पना चर्चित रही है।

(कारण)

मध्यम आय पाश (MIT) ऐसी स्थिति है, जब एक निम्न विकास दर वाली अर्थव्यवस्था तीव्र विकास करके मध्यम विकास दर वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लेती है, लेकिन इससे बाहर निकल नहीं पाती। अर्थात उच्च विकास दर वाली इकोनोमी नहीं बन पाती।

ब्राजील को मध्यम आय पाश में फंसी अर्थव्यवस्था का क्लासिक उदाहरण माना जाता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उत्तरदायी कारण

- विगत वर्षों में विमुद्रीकरण के कारण घरेलू माँग में कमी आयी है, जिसके उत्पादन में कमी हुई।
- जीएसटी कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।
- विश्व स्तर पर ट्रेड वार एवं मंदी के कारण भारतीय निर्यात में गिरावट होने का तर्क भी दिया गया है।
- भारत का जनांकिकी लाभांश का पूर्ण दोहन न कर पाना तथा सक्षम भारतीय राज्यों की जनसंख्या का गिरता लाभांश।
- नीतिगत फैसले जैसे BS IV से सीधे BS VI अपनाना जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी का दौर एवं उत्पादन में कमी।

भारत द्वारा बचाव हेतु उपाय

- निवेश: भारत को निजी व सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना चाहिए। नीति आयोग की "strategy for New India@75"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

में निवेश को वर्ष 2022 तक 36% बढ़ाने की वकालत

- निर्यात :- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात को बढ़ाना।
- श्रम सुधारों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि।
- जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने हेतु कौशल, स्वास्थ्य एवं रोजगार पर जोर
- ऊर्जा संरक्षण एवं जल संरक्षण तकनीकों पर जोर।
- बचत की प्रवृत्ति को उत्पादक कार्यों में लगाना।

हम कह सकते हैं कि MIT से बचने हेतु भारत को समग्र एवं प्रभावी रणनीतियों की जरूरत है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Highlighting its importance, discuss the major issues that plague effective monetary policy transmission in India. Also, mention the steps taken by RBI to improve it. **(250 words) 15**

भारत में मौद्रिक नीति संचरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए जो इसकी प्रभाविता को बाधित करते हैं। साथ ही, इसमें सुधार के लिए RBI द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

मौद्रिक नीति का संचरण, RBI द्वारा किया जाता है। इसमें विनिमय दरों का संतुलन, खुले बाजार की क्रियाएँ इत्यादि शामिल है।

महत्व

- तरलता का निर्धारण - RBI रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से बाजार की तरलता निर्धारित करता है।
- मँहगाई पर नियंत्रण - मँहगाई पर बढ़ने पर रेपो रेट में वृद्धि की जाती है।
- इसके अलावा बेहतर बैंकिंग तंत्र सुनिश्चित करने हेतु CRR, SLR की व्यवस्था मौद्रिक नीति का अंग है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

- इसके अलावा खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से RBI तरलता निर्धारण करता है।

निम्न मुद्दे मौद्रिक नीति संचरण को बाधित कर रहे हैं:-

- सरकारी हस्तक्षेप के कारण दीर्घकालीन लक्ष्यों को बाती। (eg) रिजर्व मानता

- RBI द्वारा बैंक रेट घटाने पर भी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दरों को कम न करना जिससे ग्राहकों को शीघ्र लाभ न मिल पाना।

- महंगाई निम्न/नियंत्रण में रहने पर भी RBI द्वारा कभी-कभी दरों को कम न करना।

- रिजर्व संबंधी मामलों में सरकार व RBI की बीच असहमति।

सुधार के लिए RBI द्वारा उठाए गए कदम

- मँहगाई का मात्रात्मक लक्ष्य 4±2% रखा जाना।
- विमल जालान समिति का गठन ताकि रिजर्व संबंधी मामलों को निपटान किया जा सके।
- रेपो रेट घटाने पर इसका लाभ तुरंत ग्राहकों तक पहुँचे इस हेतु सरल विधान।
- खुले बाजार की क्रियाओं हेतु online प्रक्रिया को अपनाना।

अतः RBI की मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति की पूरक है। इस हेतु इसमें अपेक्षित सुधार एवं गत्यात्मकता जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight the constraints faced by rainfed agriculture in India. Discuss some agronomic practices that can be adopted for stabilizing agricultural production in rainfed areas. **(250 words) 15**

भारत में वर्षा सिंचित कृषि में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिए। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु अपनाई जा सकने वाली कुछ कृषि-वैज्ञानिक पद्धतियों की चर्चा कीजिए।

भारतीय कृषि मानसूनी जुआ है क्योंकि यह मानसून की गति एवं प्रवृत्ति पर निर्भर करती है।

भारत में वर्षा सिंचित कृषि में आने वाली बाधाएँ निम्न हैं:-

- अनियमित, अनिश्चित वर्षा होने की फसलों को कभी जलाभाव का सामना करती हैं; तो कभी जल आधिक्य का। (eg) पश्चिमी भारत व नम पूर्वी भारत।

- वर्षा जल संरक्षण तकनीकों के अभाव को भौम जल स्तर नीचे होने से जल का लंबे समय तक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

तालाबों में न रहना (vg) के कारण।

- परंपरागत जल संग्रहण प्रणालियों यथा झील, झरने, तालाब इत्यादि पर अतिक्रमण के कारण वर्षा जल का कृषि कार्यों में उपयोग न होना।

- जन-जागरूकता के अभाव के कारण वैज्ञानिक पद्धतियों को न अपनाना।

इसीलिए इन क्षेत्रों कृषि - वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है:—

- सूक्ष्म सिंचाई की मदद से सिंचाई व जल उपलब्धता में वृद्धि होने से फसल उत्पादन में स्थायित्व व वृद्धि।

- स्प्रिंकलर पद्धति भी बागवानी में जल दक्षता बढ़ा सकती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- जोहड़, टँका, चाक जैसी परंपरागत पद्धतियों को वैज्ञानिक ज्ञान की मदद से अधिक समावेशी भी बनाया जा सकता है।

- इसी अनुसंधान एवं विकास पर बल देने की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक सिंचाई पद्धति वर्तमान समय की माँग है, तभी कृषकों की 2022 तक आमदनी दुगुनी हो पाएगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Despite the steps taken by the government in recent years, a number of problems continue to persist in the urea sector in India. Discuss. What reforms should be taken to address the persisting problems?

(250 words) 15

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद, भारत में यूरिया क्षेत्र में कई समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। चर्चा कीजिए। मौजूदा समस्याओं के समाधान हेतु क्या सुधार किए जाने चाहिए?

वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यूरिया क्षेत्र में कई कदम उठाये हैं। जो इस प्रकार हैं:-

- नीम-लेपित यूरिया का प्रयोग करके एक तरफ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है; वहीं इसकी दक्षता को भी बढ़ाया है।

- यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचाया गया है। (DBT - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) ताकि उपयोग न्यूनतम किया जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- इस पर देनी जाने वाली सब्सिडी को भी तर्कसंगत बनाकर इसे लोकोन्मुख बनाया जा रहा है।
- ताकि राजकोषीय घाटा को भी संतुलित किया जा सके।
- यूरिया बोरी का वजन 50kg से घटाकर 45kg (किया)

लेकिन उपरोक्त सुधारों के बावजूद निम्न चुनौतियाँ विद्यमान है :-

- यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी अब भी राजकोषीय घाटे का कारण बनी हुई है।
- कालाबाजारी एवं जमाखोरी की प्रवृत्ति के कारण जरूरत के समय यूरिया नहीं मिल पाता।
- वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँच न होना।
- जागरूकता के अभाव में अत्यधिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

यूरिया का इस्तेमाल जिससे संसाधनों के अपव्यय के साथ-साथ मृदा प्रदूषण की समस्या है।

समाधान हेतु सुधार

- बड़े किसानों को सब्सिडी छोड़ने हेतु प्रोत्साहित करना।
- लघु एवं सीमांत किसानों के खाते में सब्सिडी स्थानांतरित करने हेतु भू-रिकॉर्ड्स का आधुनिकीकरण।
- SHC बनाने हेतु जगह-जगह कैम्प लगाना।
- एकीकृत यूरिया नीति को अपनाना।

अतः यूरिया के प्रयोग को दक्षता बढ़ाकर वर्तमान कृषि संकट का समाधान करने की तरफ बढ़ा जा सकता है।

16. What is Access and Benefit Sharing? Explain how it aids in sustainable use of biodiversity. Also, mention the different global and national level mechanisms for ensuring Access and Benefit Sharing. **(250 words) 15**

पहुंच और लाभ साझाकरण (एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग) क्या है? यह जैव विविधता के संधारणीय उपयोग में किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही, पहुंच और लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रणालियों का उल्लेख कीजिए।

नागोया प्रोटोकोल तथा जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जैव संसाधनों तक सभी की समान पहुँच तथा उससे अर्जित लाभों का समतामूलक वितरण ही 'एक्सेस एण्ड बेनिफिट शेयरिंग' है।

'एक्सेस एण्ड बेनिफिट शेयरिंग' का जैव विविधता के संधारणीय उपयोग में सहायता :-

- यह सुनिश्चित करती है कि जैव विविधता तक सभी की पहुँच हो।
- साथ ही साथ जैव विविधता का ऐसा संधारणीय उपयोग किया जाए

जो पर्यावरण उपभोगों को न्यूनतम रखते हुए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

- इस हेतु नगोया प्रोटोकॉल (जैव विविधता कन्वेंशन 1992) पारित किया गया।
- इसमें आनुवंशिक रूप से उत्पन्न जीवों से भी जैव विविधता संरक्षण पर जोर देकर उसके सतत उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।

'पहुँच व लाभ साझाकरण' हेतु प्रणालियाँ :-

राष्ट्रीय प्रणालियाँ

- भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया जो त्रिस्तरीय ढाँचे का संचालन करता है।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBDA)

वैश्विक प्रणालियाँ

- जैव विविधता कन्वेंशन जो जैवविविधता के सतत उपयोग को बढ़ावा देकर पहुँच व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

↓
SBDA
↓
जैव विविधता समितियाँ

लाभ साझाकरण पर ज़ोर देती है।

• भारत में जन-जागरूकता के माध्यम इस दिशा में जैव विविधता स्थल व मिशन इन इंडिया लॉन्च किया है।

• यूनेप व IUCN ने हाल ही में इस हेतु नवीन संधि की है।

सारांशतः जैवविविधता तक सभी को समान पहुँच तथा उसके लाभों का सभी में समतामूलक वितरण होना चाहिए ताकि न्यायपूर्ण विश्व की संकल्पना साकार हो सके।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Stating the significance, discuss the challenges in achieving disaster resilience of infrastructure. Suggest some ways for mainstreaming it in the development paradigm. **(250 words) 15**

अवसंरचनाओं का आपदाओं के प्रति सुनम्य (रेजिलिएंट) होने के महत्व को स्पष्ट करते हुए, इससे संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिए। इसे विकास प्रतिमान की मुख्यधारा में लाने हेतु कुछ उपाय सुझाइये।

आपदा ऐसी महाविनाशकारी घटना है जो जान-माल का व्यापक नुकसान करती है और समाज इससे स्वयं उबरने में सक्षम नहीं होता है।

अवसंरचनाओं का आपदाओं के प्रति सुनम्य होने का महत्व:

- अगर अवसंरचना मजबूत है तो आपदाओं के कारण जान-माल का न्यूनतम नुकसान होगा। यथा- आपदारोधी विशेषकर भूकंपरोधी मकान।

- मजबूत अवसंरचनाएँ आपदाओं के दौरान शरणस्थली व आश्रय का काम करती हैं। यथा- बहुउद्देशीय चक्रवात स्थल।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

• कमजोर अवसंरचना कम तीव्रता की आपदा में भी गंभीर नुकसान पैदा करती है। → नेपाल में आया 2015 का भूकंप।

चुनौतियाँ

• भारत जैसे विकासशील देशों में आपदा पूर्व निवेश तथा मजबूत अवसंरचना की का अभाव।

• नगर-निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण नक्शों का आसानी से पास होना।

• लोगों का घर बनाते समय ढांचे के मजबूतीकरण से बचना।

• सरकारी नीतियों में आपदारोधी अवसंरचना से ज्यादा आपदा बचाव पर जोर।

• जन-जागरूकता की कमी से भूमि संसाधनों का कुप्रबंधन भी कमजोर अवसंरचना को जन्म देता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अवसंरचना मजबूती को विकास प्रतिमान की मुख्य धारा में लाने हेतु उपाय निम्न है: -

- एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (AMCDRR 2016) में प्रधानमंत्री द्वारा जारी 'दस बिन्दु कार्ययोजना' को लागू करना।
- सेंदाई फ्रेमवर्क (SFDRR 2015-30) के अनुरूप मजबूत अवसंरचना निर्माण।
- निजी क्षेत्र द्वारा CSR गतिविधियों के माध्यम से आधारभूत ढाँचे पर निवेश
- जन-जागरूकता के माध्यम (सोशल मीडिया, NGO आदि) से लोगों मजबूत घरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप भवन-निर्माण।

सार यही है कि मजबूत अवसंरचना आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों को न्यूनतम कर देती है।

18. Highlighting the significance of data localization for India, discuss various challenges associated with data localization. **(250 words) 15**

भारत के लिए डेटा के स्थानीयकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डेटा के स्थानीयकरण से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

डेटा स्थानीयकरण से तात्पर्य डेटा का स्वदेश में ही संग्रहण, प्रसंस्करण तथा भंडारण से है।

डेटा स्थानीयकरण का महत्व :-

- निजता का मौलिक अधिकार (Art.21) इसे देश में ही भंडारित करने पर बल देता है ताकि मानवाधिकारों का सम्मान हो।

- बी. एन. कृष्णा समिति के अनुसार डाटा चूंकि पूंजी है अतः इसका देश में ही भण्डारण आवश्यक है।

- वर्तमान वैश्वीकरण के युग में नीति-निर्माण, सतत विकास हेतु नीतियाँ बनाने में डाटा की आवश्यकता

है।

- विदेश में डाटा संग्रहित होने पर 'डाटा उपनिवेशवाद' की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

- लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रुचियों संबंधी डाटा को बेच देने से उनका व्यवसायीकरण होता है।

- कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक यूजर्स के डाटा का प्रयोग इसका ज्वलंत उदाहरण है।

लेकिन डेटा स्थानीयकरण से जुड़ी चुनौतियां निम्नलिखित हैं: —

- फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों का तर्क है कि इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी।

- इसके कारण उपभोक्ता सेवाओं को बहनीय व किफायती कीमतों पर

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पहुँचाना मुश्किल होगा।

- इन कंपनियों के सर्वर भी विदेशों में स्थित है।
- आवश्यक अवसंरचना का अभाव।

समाधान

- इस हेतु एक कॉपी भारत में ही भण्डारित करने को अनिवार्य बनाना जाना चाहिए।
- साथ ही डाटा संरक्षण पर B.N. श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

कुल मिलाकर वर्तमान साइबर असुरक्षित विश्व में डाटा लोकलाइजेशन महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Money Laundering as a socio economic offence is a menace especially for developing countries like India. Comment. What measures have been taken at the domestic and international levels to deal with this menace?

(250 words) 15

एक सामाजिक आर्थिक अपराध के रूप में धन शोधन विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक खतरा है। टिप्पणी कीजिए। इस खतरे से निपटने हेतु घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं?

धनशोधन एक सामाजिक एवं आर्थिक अपराध है। यह समाज में नशाखोरी, जनांकिकी लाभांश को निष्क्रियता तथा काला धन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है।

भारत के लिए खतरा

- काले धन को बढ़ावा देता है।
- हवाला के जरिए भूमिगत अर्थव्यवस्था को पैदा करता है।
- सरकार को टैक्स न मिल पाने के कारण राजकोषीय क्षति होती है।
- साथ ही साथ मादक पदार्थों की, हथियारों की अवैध खरीद-तस्करी, फिरौती को भी बढ़ावा मिलता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

• समाज में कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य के खर्च करने की क्षमता में कमी आती है।

इसीलिए इस खतरे से निपटने हेतु 'दोहरी रणनीति' की आवश्यकता है :-

घरेलू स्तर पर

• प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2005 (PMLA) के प्रावधानों का ठोस कार्यान्वयन

• IT का प्रयोग
बड़े - लेनदेन हेतु PAN, आधार को अनिवार्य करना

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग के विरुद्ध तीव्र कार्यवाही

• विभिन्न देशों के बीच दोहरा कराधान संधि (DTAA) का अधिकतम विस्तार

- विदेशी मुद्रा संशोधन अधिनियम को प्रभावी बनाना।

- पुलिस तंत्र एवं खुफिया तंत्र की मजबूती ताकि घटना घटित होने पर तुरंत कार्यवाही की जा सके।

- विभिन्न देशों द्वारा UNO के माध्यम से मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून को पारित करवाना ताकि वैश्विक एकजुटता पैदा की जा सके।

इस प्रकार मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु बहुआयामी प्रयासों की जरूरत है; तभी सामाजिक व आर्थिक रूप से सुरक्षित विश्व व राष्ट्र का सपना साकार होगा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. The primary motive of terrorism differs from that of organised crime but there exists a symbiotic relationship between the two. Discuss.

(250 words) 15

आतंकवाद का प्राथमिक उद्देश्य संगठित अपराध के उद्देश्य से भिन्न होता है, किन्तु दोनों के मध्य एक सहजीवी संबंध पाया जाता है। चर्चा कीजिए।

आतंकवाद मानवता के लिए ऐसा नृशंस कृत्य है, जिसमें निर्दोष लोगों को डराया धमकाया जाता है तथा उनकी हत्या कर दी जाती है ; वहीं दूसरी तरफ संगठित अपराध एक निश्चित पदानुक्रम तथा शक्ति - स्रोत से संचालित अपराध प्रक्रिया है।

आतंकवाद बनाम संगठित अपराध :- (भिन्नता)

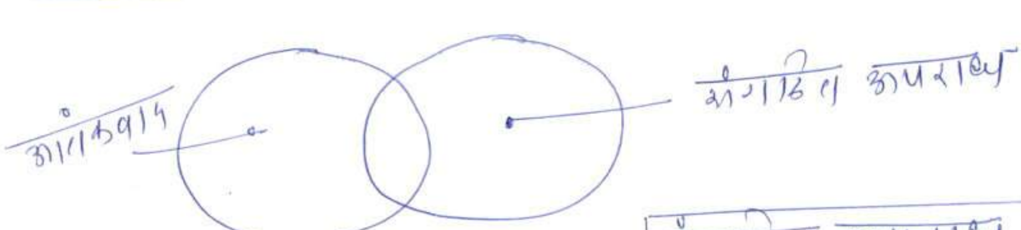

आतंकवाद	संगठित अपराध
• इसका उद्देश्य भय पैदा करना एवं मानवता को नष्ट करना है।	• इसका उद्देश्य धन एकत्र करना तथा आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित करना हो सकता है।

• आतंकवाद मनमाने एजेंडे को लागू करने हेतु की गई घृणित कार्यवाही है।	• संगठित अपराध लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही है।
• 26/11 मुंबई हमला, क्राइस्टचर्च बम धमाके 2019 (न्यूजीलैंड)	• दाऊद इब्राहिम की 'डी कंपनी'

लेकिन दोनों में कुछ समानताएँ भी हैं, जो इन दोनों के मध्य सहजीवी संबंधों का निर्धारण करती हैं :—

- दोनों ही हिंसा, हत्या, गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं।
- संगठित अपराध से एकत्रित धन आतंकवादी हमलों में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे - ISIS द्वारा फिरौती

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

से एकत्र धन तथा बाद में उसका आतंकी कृत्यों में इस्तेमाल।

- कभी-कभी आतंकवाद से उत्पन्न दशहत संगठित अपराध को भी बढ़ावा देती है। उदा० 1993 के मुंबई बम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम के D-कंपनी का संगठित अपराध के रूप में उभार

समाधान

- दोनों के समाधान हेतु - बेहतर सीमा प्रबंधन, सीमावर्ती इलाकों में बेहतर अवसंरचना का विकास।
- FATF की ग्रे लिस्ट व ब्लैक लिस्ट द्वारा आतंकी वित्तपोषण पर लगाम
- बेहतर खुफिया समन्वय।

अतः आतंकवाद एवं संगठित अपराध के असामाजिक तत्व एक दूसरे को खाद-पानी का काम करते हैं।